राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

योजना विभाग

चौथा स्तर, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली -110002

तारांकित प्रश्न संख्या- विधान सभा मौखिक उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न 104.

दिनांक - सोमवार २६ मार्च २०१८/ ०३ चैत्र १९३९ (शक)

प्रश्न कर्ता का नाम- श्री अजय दत्त

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	पिछले 10 वर्षों में कितनी बार 'आउटकम बजट' पेश किया गया ?	आउटकम बजट दिल्ली सरकार ने बजट भाषण के दौरान केवल २०१७-१८ में प्रस्तुत किया । इसकी प्रतियाँ बजट भाषण के पश्चात् माननीय विधायकों को वितरित की गई थी ।
2.	क्या भारत में किसी सरकार ने 'आउटकम बजट' पेश किया है ?	जी हाँ।
3.	सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 'आउटकम बजट' में कितने इंडिकेटर चिन्हित किए गए ?	आउटकम बजट २०१७-१८ में कुल 1069 आउटपुट इंडिकेटर और 869 आउटकम इंडिकेटर है।
4.	पिछल 10 वर्षों में 'आउटकम बजट' को रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्री के स्तर पर कितनी बैठकें की गई ?	पिछले दस वर्षों में केवल वर्ष २०१७-१८ में ही माननीय मुख्यमंत्री और मेरे स्तर पर 40 बैठकें आयोजित की गईं।

(मनीष देव)

उप निदेशक (मोनिटरिंग)

पूरक सामग्रा

विधान सभा

मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न श्री अजय दत्त ता 104.

सोमवार, 26 मार्च, 2018 / 03 चैत्र, 1939(शक)

1. दिल्ली सरकार वर्ष २००६-०७ से आउटकम बजट बना रही है (२०११-१२, २०१२-१३ एंड २०१६-१७ को छोड़कर) किन्तु विधायकों को बांटा नहीं जाता था। आउटकम बजट वर्ष केवल २०१७-१८ में, माननीय उप मुख्यमंत्री के बजट भाषण के अनुसार सभी माननीय विधायकों को वितरित किया गया था ।

2. जी हां, वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या F.No.2(1)Pers/E-Coord/OB/2005 दिनांक ३० दिसंबर २००५ के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग आउटकम बजट बना रहे है, इसी प्रकार राज्य सरकारें भी आउटकम बजट तैयार करती है।

3. दिल्ली सरकार वर्ष २००६-०७ से आउटकम बजट बना रही है (२०११-१२, २०१२-१३ एंड २०१६-१७ को छोड़कर)। पिछले आउटकम बजट सूचक में, भौतिक आउटपुट थे और संकेतक नहीं थे तथा जिसमें सभी भौतिक आउटपुट संख्यात्मक रूपों में नहीं थे।

4. पिछले दस वर्षो में माननीय मुख्यमंत्री, योजना मंत्री और मुख्य सचिव द्वारा की गई योजना समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओ/ कार्यक्रमों के भौतिक परिणाम पर चर्चा की जाती थी। पिछले दस वर्षों में आउटकम बजट को रिव्यु करने के लिए, केवल वर्ष २०१७-१८ में ही माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री स्तर पर 40 बैठकें आयोजित की गईं।